समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों का आवासों का आवंटन

1381. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को आवास देने के लिए क्या योजनायें तैयार की हैं और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को मकान मुहैया करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न आश्रय योजनायें तैयार की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना (31-1-90 तक) के दौरान हुई प्रगति इस प्रकार है :—

(लाखों में)

योजना	उपलब्धियां	
	छठी योजना	सातवीं योजना (31-1-90 तक)
राज्य क्षेत्र		
1. ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास-स्थल का प्रावधान (परिवार)	54.33	41.38
2. निर्माण सहायता (परिवार)	19.13	20.77
3. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग आवास (शहरी क्षेत्र) (रिहायशी एकक)	8.27	6.71
केन्द्रीय क्षेत्र		
4. इन्दिरा आवास योजना (रिहायशी एकक)	प्रारम्भ नहीं की गई	6.08

5. पटरी निवासी योजना

यह योजना 1988-89 में प्रारंभ की गई थी । मद्रास, हैदराबाद और कलकत्ता में 5040 पटरी पर रहने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए और 1360 व्यक्तियों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करने के लिए 298.92 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है ।

Punctuality in the running of trains

1382. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether punctuality in the running of trains has been badly affected during the past two-three months;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the details of the long distance trains which could not maintain punctuality during the last three months; and

(d) the steps taken by Government to maintain punctuality in running of the trains?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) Punctuality of trains suffered a set back due to anti reservation agitation and bad weather during November, December' 89 and January' 90.

(c) Tamilnadu, Kerala, Andhra Pradesh, Neelanchal|Puri, Magadh, Vaishali and Rajdhani Expresses were some of the long distance trains whose punctuality has not been satisfactory.

(d) Intensive chasing, monitoring and punctuality drives.

Farm strategies for better land use system

1383. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether some renowned agricultural scientists had called for reorienting farm strategies to face challenges of the 1990 through better land use system;

(b) whether the Indian Council of Agricultural Research proposes to make better use of land to improve farm strategies; and

(c) if so, the steps Government propose to take in this regard?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL): (a) Yes, Sir.

(b) Yes.

(c) The research programmes of the Indian Council of Agricultural Research and State Agricultural Universities have been reoriented for developing better land use management systems.

उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजदूर

1384. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कितने खेतिहर मजदूर हैं ;

(ख) उनकी दशा में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या उन पर जीवन बीमा योजना लागू की जाएगी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) भारत की जनगणना, 1981 के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 51.8 लाख खेतिहर मजदूर थे ।

(ख) खेतिहर मजदूरों को लागू विभिन्न श्रम कानूनों के अलावा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना जैसे गरीबी-निवारण कार्यक्रमों के जरिये राज्य के गरीब वर्गों को मजदूरी रोजगार और स्व-रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूर शामिल हैं। 1988-89 और 1989-90 (सितम्बर, 1989 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खेतिहर मजदूरों के क्रमशः 1.75 लाख और 0.97 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की गई है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को वर्ष 1989-90 के लिए 51706.13 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है और फरवरी, 1990 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1266.28 लाख श्रम दिव के रोजगार का सृजन किया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 जनवरी, 1988 से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय सरकार की ग्रुप बीमा योजना को लागू किया है । 30 सितम्बर, 1989 तक, इस योजना के अधीन 1,333 परिवारों को लाभ प्राप्त हुए थे ।

Involvement of State Governments for raising funds for construction of new railway lines

1385. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have taken a policy decision to involve State Governments in raising funds for the construction of new rail lines;

(b) if so, whether Government have asked all State Governments to share the construction of new rail lines; and

(c) whether any State Government has agreed to the said proposal; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No such general decision has been taken. However, in case of Mankhurd-Belapur project in Maharashtra, the State Govt. is contributing through CIDCO funds to the extent of 67 per cent. In case of new Konkan Railway project the four concerned State Govts. are also likely to contribute funds.

(b) and (c) Do not arise.

Defining the term of weaker sections of the society

1386. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Supreme Court has recently directed the Central Government to define the term 'weaker sections of the society' and also that appropriate guidelines be laid down;

(b) if so, whether the Union Government have since taken any steps so far to define the said term and to lay down appropriate guidelines; and

(c) if so, the details thereof?